शुरूआत के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता।

– अज्ञात

अभियान सवालों के घेरे में

दोनों ही मामलों में हालत आधे भरे गिलास जैसी है। सद्दाम हुसैन, ओसामा बिन लादेन, मुल्ला उमर और अल बगदादी मारे जा चुके हैं। अलकायदा और बाद में उभरे आइसिस का ढांचा भी ध्वस्तप्राय है।

नवीन जोशी।

नया साल शुरू होने से ठीक पहले दो ऐसी घटनाएं हुईं जिनसे आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का दो दशक लंबा अभियान सवालों के घेरे में आ गया है। 31 दिसंबर, यानी बीते मंगलवार को इराक की राजधानी बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर उग्र प्रदर्शनकारियों की भीड़ चढ़ दौड़ी। ये लोग ईरान समर्थित मिलिशिया के खिलाफ अमेरिकी हवाई हमलों से नाराज थे। अमेरिका ने इस औचक गतिविधि के पीछे ईरान का हाथ बताया और दोनों देशों में जुबानी जंग छिड़ गई। इसके दो दिन बाद प्रदर्शनकारी अमेरिकी दूतावास परिसर से पीछे हट गए लेकिन तब तक जो हो चुका था, उससे इराक में अमेरिका की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी घटना इससे एक दिन पहले अफगानिस्तान में घटित हुई, जहां तालिबान के हमले में 14 अफगान सैनिकों की जान चली गई। यह कोई अलग–थलग घटना नहीं है। बीते साल में तालिबान और आइसिस के कई हमले अफगानिस्तान में देखने को मिले हैं। अलबत्ता सोमवार को हुए हमले की अहमियत इस बात में है कि हफ्ता भर पहले अमेरिका और तालिबान में समझौते की बातचीत आखिरी चरण में बताई जा रही थी। समझौते पर दस्तखत के लिए अमेरिका की शर्त युद्धविराम घोषित करने की थी।

खबरों के मुताबिक तालिबान इसके लिए सैद्धांतिक सहमति भी दे चुका था। इसके बावजूद उसके द्वारा इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई के गहरे निहितार्थ हैं। इस हमले में किसी अमेरिकी सैनिक की जान नहीं गई है, लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका के लिए इस चुनावी साल में अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस लाना आसान नहीं होगा।

देखा जाए तो आतंक के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के दो बड़े लक्ष्य थे– इराक और अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के ढांचे को नेस्तनाबूद करना, साथ ही पश्चिमी एशिया में अपना और अपने खास दोस्त सऊदी अरब का वर्चस्व कायम करना। दोनों ही मामलों में हालत आधे भरे गिलास जैसी है। सद्दाम हुसैन, ओसामा बिन लादेन, मुल्ला उमर और अल बगदादी मारे जा चुके हैं। अलकायदा और बाद में उभरे आइसिस का ढांचा भी ध्वस्तप्राय है। लोन वुल्फ कहलाने वाले कुछ अलग–थलग आतंकी भले ही जब–तब अपनी हरकतों से दुनिया को चौंकाते रहें, लेकिन योजना बनाकर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की हालत उनकी नहीं बची है।

बावजूद इसके, अफगानिस्तान पर तालिबान अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और अमेरिका लाख चाहकर भी वहां से अपनी जान नहीं छुड़ा पा रहा। दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन का सत्ता ढांचा उखड़ जाने और बशर अल असद का दायरा सिमट जाने के चलते धुर अमेरिका विरोधी शक्ति ईरान को अपने प्रभाव विस्तार के लिए इराक और सीरिया जैसे दो देश मिल गए हैं। ऐसे में पश्चिमी एशिया और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की चुनौतियां इतनी बढ़ गई हैं, जितनी अरब–इजराइल युद्ध के बाद कभी नहीं थीं। तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ने इतनी लंबी लड़ाई क्या घाटा उठाने के लिए लड़ी?

जीवन क्या है?

धर्म-दर्शन

योगाचार्य सुरक्षित गोस्वामी। गीता में कहा है कामना रहित होकर रहो ! इसका क्या अर्थ है ? उत्तरः हमारी दिन–प्रतिदिन की बढ़ती कामनाए कभी पूरी नहीं होती बल्कि हम ही पूरे हो जाते है ! कामना का अर्थ है असंतुष्टि ! कामनाओं को ज्यादा बड़ा न बनाने दो नहीं तो उसकी पूर्ति के लिए बार–बार किसी न किसी के आगे गिड़गिडाना ही पड़ेगा ! जीवन में हमेशा कर्म को प्रधान बनाओ तो आपको अपने आप सब कुछ मिलता चला जाएगा ! इसलिए कहा है कि कामनाओं के भरोसे जीवन न जीयो बल्कि इनका त्याग करने का प्रयास करते रहो ! देखो अपनी–अपनी प्रारब्ध के अनुसार सबको भोग के लिए ये बहुत कुछ मिला है और जो भी मिला जितना भी मिला वो पहले से ही तय था !

संपादकीय

शिक्षा की असलियत

सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। कुछ व्यावहारिक अड़चनें दूर हो जाएं तो इसका लाभ प्राइवेट सेक्टर के करोड़ों कर्मचारियों को मिलेगा। अभी सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन के बीच कोई तुलना नहीं है। अच्छी–खासी तनख्वाह पाने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी पेंशन नाममात्र ही मिलती है।

सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जो उसने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दी थी। केरल हाईकोर्ट ने रिटायर हुए सभी कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देने का आदेश दिया था, जबकि अभी ईपीएफओ द्वारा 15,000 रुपये के बेसिक वेतन की सीमा के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद निजी कर्मचारियों के पेंशन की गणना पूरे वेतन के आधार पर होगी। देश में नई अर्थनीति लागू होने के बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी चिंता भी सामने आई, हालांकि सरकार इसे लेकर हमेशा उलझन में ही रहती आई है। 1995 में उसने संगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ईपीएस शुरू की थी जिसमें कंपनी को कर्मचारी के मूल वेतन का 8.33 प्रतिशत हिस्सा जमा करना होता था। फिर इसे 6,500 रुपये का 8.33 पर्सेंट कर दिया गया। इसके बाद नियमों में बदलाव करते हुए कहा गया कि कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से अपनी सैलरी का जितना भी हिस्सा चाहें, पेंशन फंड में जमा कर सकते हैं। यह भी तय किया गया कि जो लोग पूरी सैलरी पर पेंशन चाहते हैं, उनका पेंशन योग्य वेतन पांच साल का औसत मासिक वेतन माना जाएगा।

हिंसक प्रदर्शन में लोगों को जेलों में ठूंस दिया जाए। यह कैसी आजादी है? हम किस तरह की आजादी चाहते हैं। हमारा संविधान क्या ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी देता है? दक्षिण और वामपंथ की लड़ाई में देश जल रहा है।

लड़ाई में देश जल रहा

प्रभुनाथ शुक्ल।

संविधान के मूल में अभिव्यक्ति की आजादी को पूरी तवज्जों दी गई है। सवाल तब उठता है जब विचारों की आजादी हाथ में पत्थर उठा ले। बेगुनाह लोगों की मॉब लिंचिंग करे। बसों, रेलवे स्टेशनों, सार्वजनिक संपत्ति को आग के हवाले कर दे। बदले में सरकारें ऐसे लोगों के खिलाफ पोस्टर जारी कर उनकी शिनाख्त करने की अपील करें। उनके घरों पर सरकारी नोटिस चस्पा हो जाए। यूपी जैसे राज्य में पुलिस दो–चार नहीं दस–दस हजार लोगों को आरोपी बना डाले। सरकारी संपत्ति क्षतिपूर्ति की नोटिस तामिल कराई जाय। हिंसक प्रदर्शन में लोगों को जेलों में ठूंस दिया जाए। यह कैसी आजादी है? हम किस तरह की आजादी चाहते हैं। हमारा संविधान क्या ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी देता है? दक्षिण और वामपंथ की लड़ाई में देश जल रहा है। सेक्युलरवाद के नाम पर नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। विचारधाराओं के हिंसक धड़े तैयार हो गए हैं।

राष्ट्रवाद की नई परिभाषाएं निरंतर गढ़ी जा रही हैं। जेएनयू, जामिया, डीडीयू और अलीगढ़, बीएचयू, जावधपुर जैसे शिक्षा संस्थानों के हालात क्या हैं। ऐसे संस्थानों में किस तरह की

विचारधाराएं गढ़ी जा रही हैं। यह विचारणीय बिंदु है। महामना मदनमोहन मालवीय ने जिस काशी हिंदू विश्वविद्यालय को अपने खून–पसीने से सींचा। उसी बगिया में संस्कृत विभाग में एक प्रफेसर की नियुक्ति को लेकर किस तरह सांप्रदायिकता और विभाजन का खेल खेला गया। शिक्षा के मंदिर को भी सांप्रदायिकता में बांटने की साजिश रची गई, यह बेहद शर्मनाक है।

विचारधाराओं में मतभेद होना आवश्यक है। लेकिन जब बात मनभेद तक पहुंच जाती है तो हिंसा का रूप पकड़ लेती है। केरल के कन्नूर विश्वविद्यालय में जिस तरह दक्षिण विचारधारा के हिमायती राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के साथ बदसलूकी की गई वह हमारे इतिहास को कलंकित करने वाली है। सभ्य समाज में इसे कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। यह बात तब और अहम हो जाती है जब उस मंच पर जानेमाने इतिहासकार इरफान हबीब जैसी शख्सियत मौजूद हों। राज्यपाल की सुरक्षा में लगे गार्ड का बिल्ला नोंचना और राज्यपाल के साथ हुई बदसलूकी किस लोकतंत्र का हिस्सा कही जा सकती है। जिन्होंने हमें भारत जैसे देश का अनुपम गुलदस्ता सौंपा उन्हीं गांधी, नेहरु और सरदार पटेल को दक्षिण और वामपंथ में बांट कर नई परिभाषा गढ़ने को बेताब हैं। दक्षिणपंथ और वामपंथ के झगढ़े की असली वजह देश में हुए राजनैतिक परविर्तन हैं। देश में दक्षिणपंथ विचारधारा की हिमायती बीजेपी का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। जिसकी वजह से दक्षिणपंथ और वामपंथ की वैचारिक पृष्ठभूमि सियासी हिंसा दौर बढ़ रहा है। देश संविधान और विधान से चलता है। हमारे संविधान का निर्माण धर्म, पंथ, जाति, लिंग, भाषा, रंग, विचार से नहीं हुआ है। संविधान मूल में सेक्युलरवाद की अवधारणा है। उसमें दक्षिण और वामपंथ का कोई स्थान नहीं है। फिर देश को बांटने की राजनीति क्यों की जा रही है। देश में 2014 में आए राजनीतिक परिवर्तन के बाद वाम और दक्षिणपंथ की बहस अधिक तीखी हो चली है। सेक्युलरवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा वाले राज्यों में बीजेपी की जीत ने गैर बीजेपीई दलों की परेशानी बढ़ा दी है।

सूडोकु नवताल- 5218

			4				3	
		6		2		4		
		8			5			
	3						7	
7				4				9
	9						5	
			2			1		
		1		7		6		
	5				3			

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5217 का हल

7	8	5	4	2	9	6	3	1
3	6	4	1	5	7	8	9	2
9	2	1	6	3	8	7	4	5
6	5	3	2	8	4	9	1	7
1	7	2	3	9	6	4	5	8
4	9	8	7	1	5	2	6	3
2	4	7	5	6	1	3	8	9
5	3	9	8	4	2	1	7	6
8	1	6	9	7	3	5	2	4

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

इंतजार नए सेनापति का

संजय खाती। कांग्रेस और बीजेपी, दोनों राष्ट्रीय दलों को अगले साल नया पूर्णकालिक सेनापति मिल सकता है। हालांकि, उसके बाद दोनों सेनापतियों के सामने पार्टी को आगे ले जाने की चुनौती भी तुरंत होगी। अभी दोनों दलों में कार्यवाहक और अंतरिम अध्यक्ष काम कर रहे हैं। आम चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनीं लेकिन अब राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। पार्टी नेताओं के अनुसार, अध्यक्ष राहुल बनें या कोई और लेकिन इतना तय है कि पार्टी को पूर्णकालिक सेनापति चाहिए जिसके नेतृत्व में पार्टी एक ठोस और साफ नीति के साथ आगे का रोडमैप बना सके। अगर राहुल दोबारा अध्यक्ष बनते हैं तो उनके लिए खुद को साबित करने का यह आखिरी मौका हो सकता है और इसके लिए उन्हें शायद बहुत वक्त भी न मिले। वहीं, आम चुनाव में जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने होम मिनिस्ट्री का पद संभाला, तब पार्टी ने जेपी नड्डा को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया।